सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संवृद्धि दर

1066. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वर्तमान संवृद्धि दर क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संवृद्धि दर में तीव्र गिरावट आई है और इस गिरावट को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों पर मतभेद है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संवृद्धि दर में आई गिरावट में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अग्रिम अनुमान के अनुसार 1998-99 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत है।

(ख) सकल राष्ट्रीय उत्पाद की वृद्धि दर 1997-98 की 5.1 प्रतिशत से बढ़कर 1998-99 में 5.9 प्रतिशत हो गई है। इसलिए वर्तमान वर्ष में वृद्धि दर में कोई गिरावट नहीं आई है।

योजना आयोग की प्रासंगिकता

1067. **श्री रमा शंकर कौशिक:**
श्री ईश दत्त यादव:
प्रो॰ राम गोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 जनवरी, 1999 को दिल्ली में "एसोचैम" द्वारा "भारत की एक होते विश्व में क्या आर्थिक प्राथमिकताएं हैं" विषय पर आयोजित एक अभिभाषण में हाउस ऑफ लार्डस के सदस्य और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री मेघनाद देसाई द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग की क्या प्रासंगिकता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग की निम्नलिखित कारणों से प्रासंगिकता है:—

(1) गरीबी उन्मूलन, जनसंख्या नियंत्रण और पूर्ण रोजगार के राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करना,

(2) संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए,

(3) प्रतिस्पर्द्धात्मक मांगों और क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना व्यय के विवेकपूर्ण आवंटन के लिए, और

(4) आर्थिक विकास के लिए विभिन्न विशेषज्ञ/कार्य दलों की सिफारिशों पर आधारित मध्यम अवधि (पंचवर्षीय योजना) की कार्यनीति तैयार करना।

पिछड़े जिलों की पहचान

1068. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वतः पिछड़े जिलों की पहचान नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) पिछड़े जिलों के विकास हेतु सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) किसी क्षेत्र का विकास और आयोजना तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों का आवंटन करना मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, योजना आयोग ने अपनी ओर से किसी क्षेत्र को पिछड़े के रूप में विनिर्धारित नहीं किया है, तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्यों के बीच सामान्य केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयुक्त फार्मूले में पिछड़ेपन के लिए उचित भार के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाती है, इसके अलावा, विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों, जैसे कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना आदि के लिए विभिन्न राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।